भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1990
(जिसका उत्तर सोमवार, 19 दिसंबर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

रुपये का सुदृढ़ीकरण

1990. श्री के. मुरलीधरन :

श्रीमती नुसरत जहां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये का मूल्य लगातार कम हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रुपये के मूल्य को सुदृढ़ करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय रुपये के गिरते मूल्य को नियंत्रित करने के लिए एक समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रुपए का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होता है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ भू-राजनीतिक तनावों और दुनिया भर में आक्रामक मौद्रिक नीति के सख्त होने से वैश्विक पिछली वचनबद्ध राशि (स्पिलओवर) के रूप में, वित्तीय वर्ष (30 नवंबर, 2022 तक) में अमरीकी डॉलर 7.8 प्रतिशत मजबूत हुआ। जबकि चालू वित्त वर्ष में 30 नवंबर, 2022 तक रुपये में 6.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, इसने इस वित्तीय वर्ष के दौरान चीनी रेनमिनबी (10.6 प्रतिशत), इंडोनेशियाई रुपिया (8.7 प्रतिशत), फिलीपीनी पेसो

(8.5 प्रतिशत), दक्षिण कोरियाई वोन (8.1 प्रतिशत), ताइवानी डॉलर (7.3 प्रतिशत) सहित अधिकांश एशियाई समान मुद्राओं आदि में बेहतर प्रदर्शन किया है।

(ख) से (ङ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विदेशी मुद्रा बाजारों की बारीकी से निगरानी करता है और बिना किसी पूर्व-निर्धारित लक्ष्य स्तर या बैंड के संदर्भ के, विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करके केवल बाजार की व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने के लिए ही हस्तक्षेप करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, आरबीआई के प्रचालनों के परिणामस्वरूप सितंबर 2022 (निपटान आधार) तक 33.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल बिक्री हुई है।

इसके अलावा, आरबीआई ने हाल की अवधि में विनिमय दर की अस्थिरता को कम करने और वैश्विक पिछली वचनबद्ध राशि (स्पिलओवर) को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा निधियन के स्रोतों में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी, इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

• वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (ख)] और अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमा देनदारियों को 4 नवंबर, 2022 तक जुटाई गई जमा राशि के लिए नकद आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) रखने से छूट दी गई थी

• ताजा एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमा राशि को 31 अक्टूबर, 2022 तक ब्याज दरों (अर्थात ब्याज दरें बैंकों द्वारा तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमा) पर दी जाने वाली दरों से अधिक नहीं होंगी पर मौजूदा विनियमन से छूट दी गई थी

• भारतीय ऋण लिखतों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रवाहों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों से संबंधित नियामक व्यवस्था को संशोधित किया गया है।

• बाहरी वाणिज्यिक उधार सीमा (स्वचालित मार्ग के तहत) को बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है और 31 दिसंबर, 2022 तक चुनिंदा मामलों में समग्र लागत सीमा को 100 आधार अंकों तक बढ़ा दिया गया है।

• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी 1 बैंक विदेशी मुद्रा में उधार देने के लिए ओवरसीज़ विदेशी मुद्रा उधार का उपयोग बाहरी वाणिज्यिक उधारों पर लागू निर्धारणों को समाप्त करने के लिए कर सकते हैं।

• भारत से निर्यातों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई, 2022 में भारतीय रुपये में चालान, भुगतान और निर्यात/आयात के निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की है।

*****